भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1655

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना

1655. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परियोजना लागत, उत्पादन क्षमता, सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, कोयले की अपेक्षित वार्षिक आवश्यकता और चालू होने की समय-सीमा सहित ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में स्थापित की जा रही भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में अनुमोदित या कार्यान्वित की जा रही कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का परिकल्पित निवेश, उत्पादन क्षमताएं और संभावित रोजगार सृजन सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट और अन्य अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) रासायनिक उत्पादों पर आयात निर्भरता में संभावित कमी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और इसके तहत जारी की गई निधि सहित अब तक दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के संयुक्त उद्यम द्वारा ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में स्थापित की जा रही है।

विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 25,016 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को 0.66 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए)

अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके लिए वार्षिक लगभग 1.66 एमएमटीपीए कोयले की आवश्यकता होगी। कोयला मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए 1350 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। यह परियोजना मार्च 2030 तक शुरू होने के लिए निर्धारित है।

(ख) : सरकार ने दिनांक 24.01.2024 को 8,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत आठ (8) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजना/कंपनी**	**उत्पाद**	**उत्पादन क्षमता**	**निवेश (₹ करोड़)**
1	ओडिशा	भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)	अमोनियम नाइट्रेट	0.66 एमएमटीपीए	25,016
2		जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल)	डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई)	2.0 एमएमटीपीए	3,882
3	पश्चिम बंगाल	कोल गैस इंडिया लिमिटेड (सीजीआईएल)	सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी)	633.6 मिलियन एनएम^3/वर्ष	13,053
4	महाराष्ट्र	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी)	633.6 मिलियन एनएम^3/वर्ष	12,215
5		ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड (जीईएमपीएल)	डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई)	0.5 एमएमटीपीए	2,763
6		न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एनईसीएसपीएल)	अमोनियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन	0.33 एमएमटीपीए एएन + 0.10 एमएमटीपीए एच$_2$	6,976
7		न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एनईसीएसपीएल)	एथनॉल	18 केटीपीए	667
8		कार्तिकेय वायुनंदना प्राइवेट लिमिटेड (केवीपीएल)	एसिटिक एसिड	75.9 केटीपीए	793

इन 8 परियोजनाओं से लगभग 12 एमएमटीपीए कोयले को गैसीकृत करने, लगभग 65,365 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और लगभग 3,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।

(ग) : सरकार ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन की स्कीम अनुमोदित कर दी है जिसके अंतर्गत आठ (8) कोयला गैसीकरण परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। शुरू होने पर, इन परियोजनाओं से अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस (एसएनजी), इथेनॉल, हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) जैसे उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से आयात निर्भरता कम होने की अपेक्षा है। इन परियोजनाओं से आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से लगभग 16,500 करोड़ रुपये की वार्षिक विदेशी मुद्रा बचत होने का अनुमान है। उनसे घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आपूर्ति-श्रृंखला का लचीलापन बढ़ाने तथा रसायन, उर्वरक और स्वच्छ ईंधन जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की सहायता करने की भी अपेक्षा है।

(घ) : दिनांक 24.01.2024 को अनुमोदित ₹8,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत, आठ (8) कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं और दो लघु स्तर की उत्पाद-आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड की एक परियोजना वित्तीय समापन प्राप्त कर चुकी है और निर्माण चरण में है, जबकि शेष परियोजनाएं वित्तीय समापन प्राप्त करने, सांविधिक स्वीकृतियों, प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने, निविदा और परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल) को उनकी गैसीकरण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त के भाग के रूप में 235.52 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।

सरकार ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के लिए दिनांक 13.05.2026 को 37,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है। आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध किया गया है और अब तक, इस नई स्कीम के तहत किसी भी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।

****